गैर सरकारी और स्वच्छिक प्रयत्नों, जिनमें सामाजिक क्रियाशील समूह भी शामिल है, को प्रोत्साहित किया जाएगा बशर्ते कि उपयुक्त प्रबन्ध हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसरण में शुरु की गई योजनाओं में संस्वीकृति और उत्तरवर्ती मानिटरिंग से पूर्व स्वैच्छिक एजेंसियों के प्रस्तावों के मूल्यांकन प्रस्तावों के लिए अन्तर्निर्मित तन्त्र हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा मिशन कार्यक्रम

1795. **श्री ईश दत्त यादव :**
श्री कनकसिंह मोहन सिंह मंगरोला :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा मिशन कार्यक्रम को छोड़ दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन कारणों की समीक्षा भी कराई है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या रहे हैं ; और

(ङ) गत तीन वर्षों में इसकी प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति

1796. **श्री अनन्तराम जायसवाल :**
श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है और प्रत्येक विश्वविद्यालय की वर्तमान आर्थिक स्थिति क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि बदहाली आर्थिक स्थिति के कारण दिल्ली विश्वविद्यालय की हालत निरन्तर बदतर होती जा रही है और शिक्षा पर इसका स्पष्ट प्रभाव पड़ रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) देश में इस समय 13 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं। स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का परिचालन व्यय योजनेतर लेखे से वहन किया जाता है।

इन विश्वविद्यालयों को जारी किए गए अनुदानों की स्थिति इस प्रकार है :-

जारी किये गये अनुदान (रु० लाखों में)योजनेत्तर-

क्र०सं०	विश्वविद्यालय का नाम	1991-92	1992-93	1993-94
1		3	4	5
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	3603.60	4119.47	5628.09
2.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	4444.07	5238.23	5883.68
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय	2501.41	2853.05	3109.78
4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	735.22	849.77	894.21

1	2	3	4	5
5.	जामिया मिलिया इस्लामिया	707.03	888.32	939.78
6.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	1403.28	1583.27	1825.29
7.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	258.01	300.21	344.82
8.	उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय	1077.77	1249.86	1319.02
9.	विश्व भारती	1041.75	1211.58	1389.39
10.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	550.00	753.00	764.60
11.	असम विश्वविद्यालय	योजनेत्तर अनुदान नौवीं योजना से ही अनुमत्य होंगे–1994 में स्थापित किये गये विश्वविद्यालयों का सारा व्यय योजनागत लेखे में है।		
12.	तेजपुर विश्वविद्यालय			
13.	नागालैंड विश्वविद्यालय			

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि गत तीन वर्षों से दिल्ली विश्वविद्यालय सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अनुदानों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। आगे यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवश्यक शैक्षणिक कार्यकलाप प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो, पुस्तकालय सुविधाओं के अनुरक्षण के लिए 1993–94 और 1994–95 के दौरान नौ करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। इसके अलावा चालू वर्ष (1994–95) के दौरान प्रयोगशाला सुविधाओं के अनुरक्षण के लिए 8.00 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान भी जारी किया गया था।

Opening of regional offices by Kendriya Vidyalayas

1797. SHRI J. S. RAJU:
SHRI SHIV CHARAN SINGH:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that three new regional offices of Kendriya Vidyalaya Sangathan had been opened in the last session;

(b) if so, whether it is also a fact that post of Assistant Commissioners have not yet been created and these offices are being headed by junior officers;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) whether the posts have since been created/being created?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KM. SELJA): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) Creation of posts in Govt. requires approval at many levels. Action to create the posts of Assistant Commissioner for the new regional offices has already been initiated.

Reconstruction of National Commission for women

1798. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the reconstitution of the National Commission for Women has been delayed;

(b) if so, how far, and the reasons therefor; and

(c) what modifications, if any, are proposed to be made to make the